

# NEXT IAS

## दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

---

भारत का शहरी बुनियादी ढांचा:  
वित्तपोषण, आवश्यकताएं और वास्तविकता

---

[www.nextias.com](http://www.nextias.com)

## भारत का शहरी बुनियादी ढांचा: वित्तपोषण, आवश्यकताएं और वास्तविकता

### सन्दर्भ

- भारत का शहरी बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है, जो देश में तेजी से शहरीकरण जारी रहने के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।
  - अगले तीन दशकों में शहरी जनसंख्या 400 मिलियन से बढ़कर 800 मिलियन होने की सम्भावना है, इन चुनौतियों का समाधान सतत शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

### भारत के शहरी बुनियादी ढांचे का वर्तमान वित्तीय परिदृश्य

- विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत को अपनी शहरी बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2036 तक लगभग 70 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
- वर्तमान में, सरकार शहरी बुनियादी ढांचे में वार्षिक लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपये का निवेश करती है, जो प्रति वर्ष आवश्यक 4.6 लाख करोड़ रुपये का एक-चौथाई से थोड़ा अधिक है।
- यह महत्वपूर्ण अंतर नवीन वित्तपोषण रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

### प्रमुख चुनौतियाँ

#### नगर निगम की वित्तीय समस्याएं:

- नगर निगम का वित्त शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन 2002 से यह सकल घरेलू उत्पाद के केवल 1% पर स्थिर रहा है।
  - देश भर में, संपत्ति कर संग्रह मात्र ₹25,000 करोड़ है, जो सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.15% है।
  - नगर निकाय शहरी निवेश में 45% का योगदान करते हैं, जबकि शेष का प्रबंधन अर्ध-सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
  - केंद्र और राज्य हस्तांतरण में वृद्धि के बावजूद, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।
- संग्रह अक्षमता समस्या को और बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु और जयपुर जैसे शहरों में शहरी स्थानीय निकाय (ULB) अपने संभावित कर राजस्व का केवल 5%-20% ही एकत्र करते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, सेवाओं के लिए लागत वसूली 20% से 50% तक होती है, जो शहरी सेवाओं की लागत और उनसे उत्पन्न राजस्व के बीच महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करती है।

### संरचनात्मक चुनौतियाँ: अवशोषण क्षमता और उपयोग के मुद्दे:

- भारतीय शहर कम अवशोषण क्षमता का सामना कर रहे हैं, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे का परिदृश्य जटिल हो गया है।
- पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, कुल नगरपालिका राजस्व का लगभग 23% हिस्सा व्यय नहीं किया जाता है, जो नगरपालिका प्रणाली में अधिशेष को दर्शाता है जिसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- हैदराबाद और चेन्नई जैसे प्रमुख शहर भी 2018-19 में अपने पूंजीगत व्यय बजट का केवल 50% ही व्यय कर पाए।
- केंद्रीय योजना निधियों का उपयोग भी वांछित नहीं है, जिसमें अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) 80% उपयोग प्राप्त कर पाया है और स्मार्ट सिटी मिशन 70% तक पहुँच गया है।

### सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) और तकनीकी एकीकरण:

- शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए PPPs को एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में पहचाना गया है।
  - हालांकि, पिछले एक दशक में PPPs परियोजनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यह शहरी बुनियादी ढांचे में निजी निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- इसके अतिरिक्त, शहरी बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की क्षमता का अभी भी कम उपयोग किया जा रहा है।

### शासन एवं योजना संबंधी मुद्दे:

- भारत में शहरी नियोजन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पुरानी स्थानिक और लौकिक योजनाएँ शामिल हैं जो जनसंख्या वृद्धि को समायोजित करने में विफल हैं।
- कई शहरी नियोजन एजेंसियाँ जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के बजाय पूंजी वृद्धि पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे स्थानीय स्वामित्व और भागीदारी की कमी होती है।
- इसके अतिरिक्त, ULBs की शासन संरचना प्रायः अकुशल होती है, जिसमें कर संग्रह और सेवाओं के लिए लागत वसूली में महत्वपूर्ण अंतर होता है।

### जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:

- जलवायु परिवर्तन शहरी क्षेत्रों के लिए एक बड़ा जोखिम बन गया है, जिससे बाढ़, लू और पानी की कमी जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं।
- अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और खराब योजना के कारण भारतीय शहर विशेष रूप से कमज़ोर हैं।
- शहरीकरण की तेज़ गति से पर्यावरण को हानि हुई है, प्रदूषण में वृद्धि और हरित क्षेत्रों के खत्म होने से शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता पर अधिक प्रभाव पड़ा है।

### सामाजिक और आर्थिक असमानता:

- भारत में शहरीकरण प्रायः आर्थिक संकट से प्रेरित रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 'गरीबी से प्रेरित शहरीकरण' हुआ है।
- इससे झुग्गी-झोपड़ियाँ और अनौपचारिक बस्तियाँ बढ़ी हैं, जहाँ रहने की स्थिति खराब है तथा बुनियादी सेवाओं तक पहुँच सीमित है।
- बढ़ती असमानता और सामाजिक अलगाव बड़ी चुनौतियाँ हैं, शहरी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के पास पर्याप्त आवास, स्वच्छ पानी एवं स्वच्छता तक पहुँच नहीं है।

### भारत के शहरी बुनियादी ढांचे की समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए सरकारी नीतियाँ

- **स्मार्ट सिटीज मिशन (2015):** इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, डेटा और नागरिक भागीदारी का लाभ उठाकर भारत भर में 100 स्मार्ट शहरों का विकास करना है, जिसमें बुद्धिमान यातायात प्रबंधन, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और बढ़ी हुई सार्वजनिक सुरक्षा जैसे स्मार्ट समाधानों के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) (2015):** यह शहरों में बुनियादी शहरी बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन और हरित स्थान शामिल हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक घर में सुनिश्चित जल आपूर्ति तथा सीवरेज कनेक्शन के साथ नल तक पहुँच हो।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - PMAY(U):** इसका उद्देश्य झुग्गी पुनर्वास, ऋण-लिंकड सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की साझेदारी में किफायती आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देकर सभी शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है।
- **राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (NUTP):** यह सतत शहरी परिवहन प्रणालियों के विकास पर जोर देती है।
  - यह यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन, गैर-मोटर चालित परिवहन एवं भूमि उपयोग तथा परिवहन योजना के एकीकरण के उपयोग को बढ़ावा देता है।
- **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (2014):** इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त बनाना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है।
  - यह शौचालयों के निर्माण, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और कुशल अपशिष्ट संग्रह एवं निपटान सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- **विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (HRIDAY):** इसका उद्देश्य भारत के विरासत शहरों को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है।
  - यह इन शहरों में बुनियादी ढांचे में सुधार, पर्यटन को बढ़ाने और विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** सरकार शहरी विकास का समर्थन करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत शहरी डेटा एक्सचेंज (IUDX) जैसी पहल शहरी नियोजन और सेवा वितरण में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करती है।

### रणनीतिक पहल

- 2019 में शुरू की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) 102 लाख करोड़ रुपये की सामाजिक और अवसंरचना परियोजनाओं पर बल देती है, जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है।
- इसके अतिरिक्त, पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को बढ़ाना है, जिससे शहरी अवसंरचना विकास को अधिक समर्थन मिलेगा।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी के माध्यम से स्थापित शहरी अवसंरचना विकास कोष (UIDF) का उद्देश्य 10,000 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय के साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का निर्माण करना है।
  - यह राज्य सरकारों को UIDF का उपयोग करते समय उचित उपयोगकर्ता शुल्क अपनाने के लिए 15वें वित्त आयोग और वर्तमान योजनाओं से संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

### तकनीकी एकीकरण

- शहरी बुनियादी ढांचे को बदलने में तकनीकी प्रगति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्मार्ट सिटीज मिशन, सतत और कुशल शहरी नियोजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बुद्धिमान बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी तकनीकों का लाभ उठाता है।
- ये प्रौद्योगिकियाँ सेवा वितरण को बढ़ाती हैं, संसाधन प्रबंधन में सुधार करती हैं और शहरी वातावरण की स्थिरता सुनिश्चित करती हैं।

## सतत विकास

- स्थिरता भारत की शहरी अवसंरचना रणनीति का आधार है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 में सतत शहरी नियोजन और विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
  - इसमें हरित पहलों को एकीकृत करना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और शहरी परियोजनाओं में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिरता के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है।

## निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत में शहरी बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें वित्तीय निवेश में वृद्धि, कुशल शासन और अभिनव समाधान शामिल हैं।
- स्थायी विकास पर ध्यान केंद्रित करके और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, भारत अपनी बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने शहरी परिदृश्य को बदल सकता है।
- बेहतर कर संग्रह और राजस्व सृजन के माध्यम से नगर निगम के वित्त को मजबूत करना, शहरों की अवशोषण क्षमता में सुधार करना और PPPs के लिए अधिक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना आवश्यक कदम हैं।
- इसके अतिरिक्त, नगरपालिका बांड और वाणिज्यिक ऋण का लाभ उठाने जैसे अभिनव वित्तपोषण तंत्र, वित्तपोषण अंतर को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

Source: TH

## दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न.** भारत के शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण की वर्तमान स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इस क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें।